



2026:AHC:66420

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4023 वर्ष 2026

कुमार सौरभ आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: संतोष कुमार केसरवानी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, शेषाद्रि त्रिवेदी

न्यायालय सं - 67

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री संतोष कुमार केसरवानी, प्रथम सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री शेषाद्रि त्रिवेदी, राज्य के राज्य विधि अधिकारी सुश्री मयूरी मेहरोत्रा को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन केस अपराध संख्या-02 वर्ष 2026 में धारा 103(1) और 3(5) बी.एन.एस., थाना सारनाथ, जिला वाराणसी के तहत मुकदमे के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क यह है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं था; बाद में सह-आरोपी युवराज सिंह के बयान में आवेदक का नाम सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वर्तमान आवेदक सह-आरोपी जितेंद्र गुप्ता के साथ उसके स्वामित्व वाले "नशा मुक्ति केंद्र" (संक्षेप में "एनएमके") का काम देखता था। इसके बाद, एनएमके के गार्ड के साथ-साथ अन्य कैदियों ने भी कहा है कि मृतक अन्य कैदियों को कमरे में बंद करने के बाद एनएमके छोड़ देता था, और इस कारण से वर्तमान आवेदक और सह-आरोपी जितेंद्र ने मृतक को छत पर ले जाने के बाद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई चोटें आईं, उसके बाद अगले दिन, मृतक की मृत्यु हो गई।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक स्वयं शराब की लत होने के कारण एनएमके में भर्ती कराया गया था, और ठीक होने के बाद वह एनएमके भी छोड़ने जा रहा था; हालांकि, इस बीच, उसे एनएमके की निगरानी करने की अनुमति दी गई थी और उस अवधि के दौरान मृतक को शराब के आदी के रूप में एनएमके में भी भर्ती कराया गया था और वह हिंसक हो जाता था और अन्य कैदियों को कमरे में बंद करने के बाद परेशान करता था; उसने एनएमके से भागने की भी कोशिश की, इसलिए, आवेदक और सह-आरोपी ने उसे लोहे के पाइप से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन गलती से मृतक को उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक स्वयं एक मरीज है, हालांकि वह शराब के अलावा ठीक हो गया था, लेकिन उस परिस्थितियों में, वह गुस्सैल और मानसिक रूप से अस्थिर हो गया, उक्त कारण से, उसने उपरोक्त कार्य किया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 03.01.2026 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. दूसरी ओर, राज्य के राज्य विधि अधिकारी के साथ-साथ पहले सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ चश्मदीद गवाहों के बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आवेदक सह-आरोपी जितेंद्र के साथ स्वयं मृतक को छत पर ले गया और उसे बेरहमी से पीटा, और कैदियों द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, वे मृतक को अस्पताल नहीं ले गए और अंततः मृतक की मृत्यु हो गई, इसलिए, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

6. पक्षों के अधिवक्ता की उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ चश्मदीद गवाह के बयान से मृतक को पीटने के लिए आवेदक की भागीदारी को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई, यह भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के खिलाफ कई सामग्रियां हैं,



इसलिए, यह न्यायालय इस स्तर पर आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है।

7. तदनुसार, ज़मानत आवेदन खारिज+ किया जाता है।

8. हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को शराब के आदी रोगी के रूप में एनएमके में भी भर्ती कराया गया था, हालांकि वह ठीक हो गया था, वह मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। उसे मनोरोग उपचार की आवश्यकता है। इसलिए, उसके बेहतर उपचार के लिए, जेल अधिकारी, वाराणसी को निर्देश दिया जाता है कि यदि आवश्यक हो, तो आवेदक को मनोरोग द्वारा जांच के बाद उचित मनोरोग उपचार प्रदान किया जाए।

मार्च 30, 2026

सीएस/-

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)